on or immediately after attainment of 7 years of age whichever is later. The period starting from the date of commencement of the policy to the commencement of risk is known as waiting period.

(c) The details of benefits and the nature of risks covered under the plan are as follows:—

(1) In case of death of the female life asseured during the waiting period the premium paid excluding the Waiver benefit will be refunded and the contract will come to an end.

(2) In case of death of the female life assured after the waiting period but before the date of maturity the full sum assured alongwith vested bonuses will be paid and the contract will come to an end.

(3) On the female life assured surviving upto the premium paying term, the full sum assured will be paid as survival benefit. The policy will however continue to participate in profits and the risk cover for full sum assured will continue upto the end of policy term even after payment of survival benefit.

(4) On the female life assured surviving upto the date of maturity only the vested bonus will be payable as the sum assured is already paid as survival benefit.

(5) After marriage of life assured the risk cover will be extended also to the life of her husband subject, however, to certain conditions. In case the husband predeceases the wife (before date of maturity then the full sum assured (without bonus) will be paid. The contract will not, however, come to an end and the risk cover on the female life assured will continue and the policy will also continue to participate in profits

Foreign Investment in the Country

884. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what was the foreign investment in India in the wake of Government's liberalised economic policy and liberalisation of regulations relating to foreign investments during the period from September, 1992 to November, 1992 and in January, 1993 with details thereof; and

(b) what are the details of withdrawal of foreign investment from India, if any during December, 1992 and January, 1993?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR ABRAR AHMED): (a) The details of foreign equity investments approved during the relevant months are as under:—

Months	Amount of total Equity
	(Rs. in millions)
September, 1992 .	1009.3
October, 1992 . .	3107.8
November, 1992 .	2717.3
January, 1993 . . Æ	8158.4

(b) No instances of disinvestment by foreign investors during December, 1992 and January, 1993 have come to the notice of the Government.

राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना

885. **श्री सोम पाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान ग्रामीण बैंक कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा दी गई इस आशय की सूचना की ओर दिलाया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं किये जाने की दशा में कर्मचारी हड़ताल कर देंगे;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करने के लिये सरकार ने 28 फरवरी, 1993 तक क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या गुप्ता पंचाट के अनुसार ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को वेतन और बकाया राशियों का भुगतान कर दिया गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इनका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ; और

(ङ) राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना से कृषकों और ग्रामीणों को क्या-क्या लाभ मिलने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ङ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन के लिये कई माडल तैयार किये गये हैं तथा सभी पहलुओं से प्रत्येक की प्रभावकारिता की जांच की जा रही है । इसमें भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक (एन.आर.बी.आई.) की स्थापना के लिये भी एक प्रस्ताव शामिल है, ताकि ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में सुधार लाया जा सके तथा ग्रामीण क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को बढ़ाया जा सके । तथापि, इस विषय में अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण (एन.आई.टी.) के अधिनिर्णय की स्वीकृति तथा समीकरण समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिये जाने पर, जिसके अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को भी प्रायोजक बैंकों के वेतनमान और अन्य लाभ प्रदान किये गये थे, सरकार ने 22-2-91 को सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आवश्यक हिदायतें जारी कर दी थीं । अधिनिर्णय के क्रियान्वयन तथा समीकरण समिति की सिफारिशों के अनुसरण में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों के लिये सेवा विनियमों, भर्ती एवं पदोन्नति नीति में कुछेक परिवर्तन किये जाने अपेक्षित थे । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने तदनुसार सितम्बर, 1991 में अपने तत्कालीन मुख्य महाप्रबंधक, श्री आर.सी.गुप्ता की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया था, जिसके विचारार्थ विषय निम्नांकित थे:-

(i) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये सेवा विनियमों को बनाना,

(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में भर्ती तथा पदोन्नति नीतियों को बनाना, और

(iii) समीकरण समिति की रिपोर्ट के साथ पठित अधिकरण के अधिनिर्णय के क्रियान्वयन के संबंध में कोई अन्य मामला ।

कार्यदल की सिफारिशों को सामान्यतया स्वीकार कर लिया गया है तथा इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिये निर्देश/अधिसूचना जारी करने के लिये आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है ।

Opening of more Bank Branches in Uttar Pradesh

886. SHRI RAM NARESH YADAV: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of branches of banks which were proposed to be opened in Uttar Pradesh during the last two years, as per the targets fixed and what were the locations thereof;

(b) what is the extent of the target achieved in this regard percentage-wise; and

(c) what are the names of the banks, the branches of which have been opened during the above period and what are their locations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. ABRAR AHMED): (a) and (b) No State-wise targets are fixed by Reserve Bank of India (RBI) for opening of branches. Under the new branch